भारत में जनगणना

वर्तमान संदर्भ:

सरकार ने वर्ष 2024 के आम चुनावों से पहले जनगणना की संभावना को खारिज करते हुए, जिलों, तहसीलों और कस्बों की प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने अर्थात, प्रशासनिक सीमाओं के परिवर्तन पर रोक लगाने की समय सीमा को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।

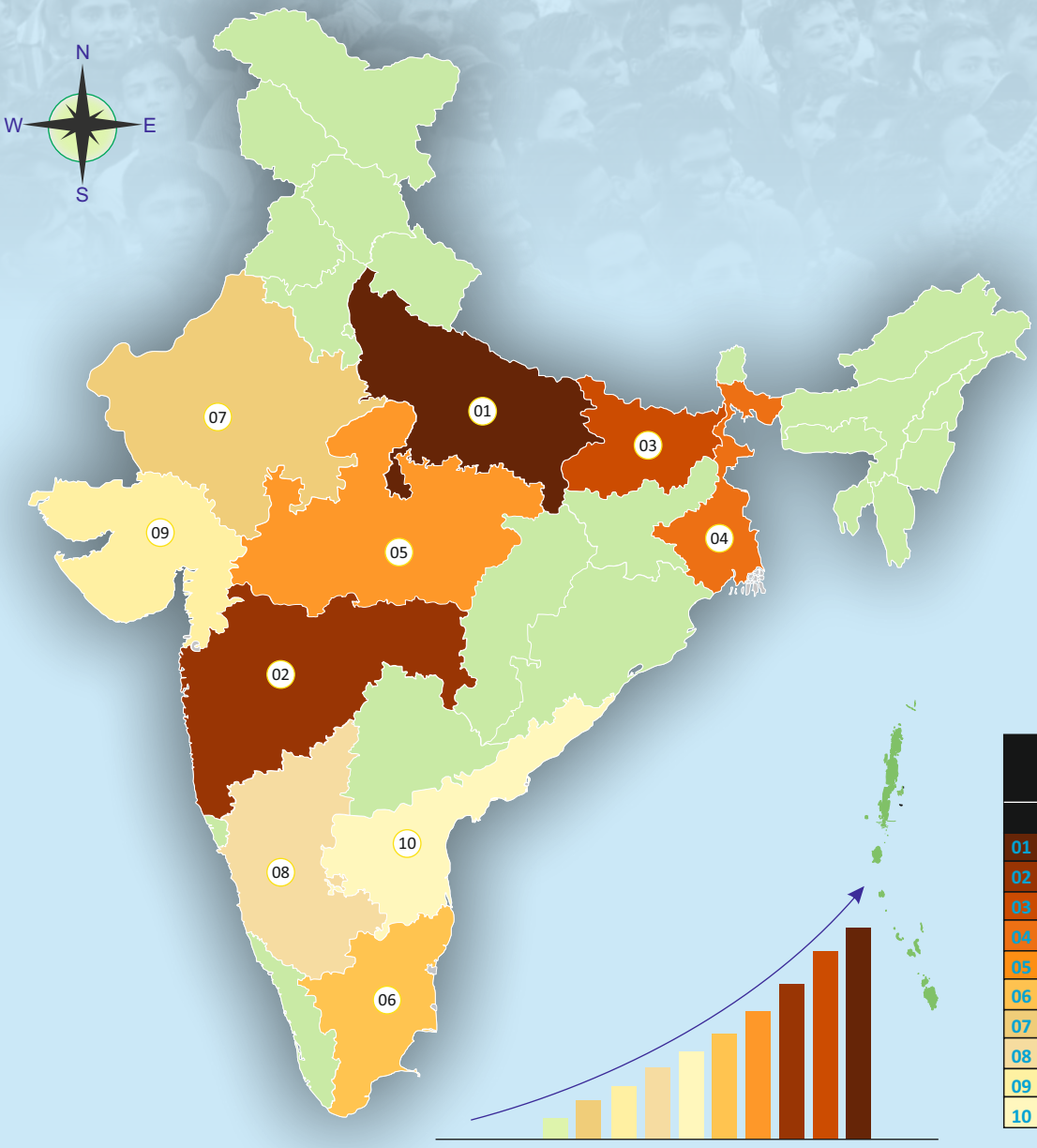

भारत के 10 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य

	राज्य	कुल जनसंख्या
01	उत्तर प्रदेश	199,812,341
02	महाराष्ट्र	112,374,333
03	बिहार	104,099,452
04	पश्चिम बंगाल	91,276,115
05	मध्य प्रदेश	72,626,809
06	तमिलनाडु	72,147,030
07	राजस्थान	68,548,437
08	कर्नाटक	61,095,297
09	गुजरात	60,439,692
10	आंध्र प्रदेश	49,386,799

जनगणना के बारे में

1. भारत में होने वाली जनगणना भारत के लोगों की विविध विशेषताओं के सन्दर्भ में विभिन्न सांख्यिकीय जानकारी का सबसे बड़ा एकल स्रोत है।

2. वर्ष 1872 में, पहली जनगणना अनियमित रूप से (अलग-अलग समय पर) की गई थी, जबकि **वर्ष 1881 में,** देश (अविभाजित भारत) के विभिन्न हिस्सों में पहली नियमित (एक ही समय पर) जनगणना की गई थी।

3. भारत की जनगणना के कार्य-संचालन का उत्तरदायित्व **भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त** कार्यालय का है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता हैं।

4. वर्ष 1951 की जनगणना तक, प्रत्येक जनगणना के लिए तदर्थ आधार पर जनगणना संगठन की स्थापना की जाती थी।

5. जनगणना अधिनियम को 1948 में अधिनियमित किया गया था, जिसमें जनगणना अधिकारियों के कर्त्तव्यो और उत्तरदायित्वों को निश्चित करते हुए जनगणना आयोजित करने की योजना का उल्लेख किया गया है।

6. जनगणना को भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 246** के तहत **संघ सूची** में रखा गया है

जनगणना का संचालन: भारत में जनगणना का संचालन दो चरणों में किया जाता है-

प्रथम चरण: मकान सूचीकरण और आवासों की गणना

- ✓ यह मानव बस्तियों की स्थिति, आवास की कमी से सम्बंधित व्यापक आंकड़े प्रदान करता है, जिसकी सहायता से आवास नीतियों के निर्माण के समय आवास आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सकता है।
- ✓ यह परिवारों को उपलब्ध सुविधाओं और संपत्तियों पर आंकड़े/सूचना की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान करता है।

द्वितीय चरण: जनसंख्या गणना

- ✓ इस चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाती है और उसके व्यक्तिगत विवरणों जैसे आयु, वैवाहिक स्थिति, धर्म, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, मातृभाषा, शिक्षा का स्तर, विकलांगता, आर्थिक गतिविधि, प्रवासन, प्रजनन क्षमता (महिला के लिए) पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।

जनगणना का महत्व:

- **सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत:** दशकीय जनगणना न केवल जनसंख्या, आवासों, परिवार इकाइयों में हुई वृद्धि को दर्ज करती है, बल्कि यह आयु, साक्षरता, प्रजनन क्षमता और प्रवासन के वितरण आदि पर **सूक्ष्म आंकड़ों का सुनियोजित संग्रह** भी प्रदान करता है।
- **कमज़ोर वर्गों का उत्थान:** संसद, राज्य विधानसभाओं, स्थानीय निकायों और सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होने वाली सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है।
- **नीतियों का आकलन:** इसके द्वारा स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) जैसे कार्यक्रमों के प्रभाव का भी आकलन किया जा सकता है।
- **सामाजिक संकेतकों का आकलन:** यह साक्षरता और शैक्षिक स्तर में सुधार, आर्थिक स्थिति संकेतकों जैसे - रोज़गार और आय का स्तर, प्रवास आदि के आकलन में उपयोगी होता है।
- **राज्यों को अनुदान:** जनगणना से उपलब्ध जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर वित्त आयोग राज्यों को अनुदान प्रदान करता है।
- भारत की जनगणना के आंकड़ों पर शोध करके हज़ारों लोगों ने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है, इसने ऐतिहासिक नीतियों (भूल और सफलता दोनों) के सन्दर्भ में नई अंतर्दृष्टि व विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त जनगणना के आंकड़ों ने राष्ट्र का एक विश्वसनीय आर्थिक इतिहास भी प्रस्तुत किया है।

2021 की जनगणना:

- कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण 2021 की जनगणना के संचालन में देरी हुई है।

विलंब के निहितार्थ:

01 **प्रवासन आकड़े :** कुछ राज्यों में हुए महामारी-प्रेरित प्रतिलोम प्रवासन या रिवर्स माइग्रेशन के विशेष सन्दर्भ में नवीनतम आकड़ों की जानकारी आवश्यक है ताकि प्रवासियों को खाद्य व अन्य सहायता पहुँचाई जा सके।

02 **सामाजिक संवितरण में अक्षमता:** जनगणना के आंकड़ों में वर्तमान विलम्ब 10 करोड़ से अधिक लोगों को अनुवृत्ति /सब्सिडी वाली खाद्य वस्तुएँ प्राप्त करने के उनके अधिकार से वंचित करने के साथ-साथ इससे सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रमशः 2.8 करोड़ और 1.8 करोड़ लोग प्रभावित होंगे।

03 सटीक जनगणना अनुमान उपलब्ध नहीं होने के कारण बुजुर्गों के लिए पेंशन जैसी कई **सरकारी योजनाएं** अपने लक्ष्य से काफी आधिक विचलित हो सकती हैं।

04 जनगणना के अभाव में विभिन्न योजनाओं के आंकड़े- जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान, स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने शौचालय इत्यादि, न होने के कारण **सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित** नहीं की जा सकती है।

05 **आयु संरचना:** महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में आयु वितरण पर इसका प्रभाव जानना रोचक होगा क्योंकि जनगणना मौतों की संख्या का अप्रत्यक्ष अनुमान प्रदान करेगा। यह महामारी के कारण होने वाली मौतों की संख्या के विभिन्न अनुमानों को या तो पुष्ट करेगा या अस्वीकार करेगा।

06 **अंतर्राष्ट्रीय छवि:** दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों ने कोविड कठिनाइयों के बावजूद अपनी जनगणना को पूरा किया है, जबकि भारत में ऐसा नहीं होने से भारत की छवि खराब हो सकती है।

2021 की जनगणना पिछली जनगणनाओं से कैसे अलग होगी?

01 जनगणना के आंकड़े डिजिटल रूप से अर्थात मोबाइल ऐप पर एकत्र किए जाएंगे, इस प्रकार ये आंकड़े प्रोसेसिंग के लिए अपेक्षाकृत जल्दी तैयार हो जाएँगे।

02 साथ ही, पहली बार स्व-गणना की सुविधा प्रदान की जाएगी।

03 उन परिवारों के मुखिया परलैंगिक (ट्रांसजेंडर) समुदाय के व्यक्ति हैं, उन परिवार में रहने वाले सदस्यों के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी।

04 प्रगणकों द्वारा उपयोग के लिए एक अलग कोड निर्देशिका तैयार की गई है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए वर्णनात्मक/गैर-संख्यात्मक प्रविष्टियों के रूप में संभावित प्रतिक्रियाएं और कोट शामिल होंगे।

जब महामारी पीछे छूट गई है, तो जनगणना में और देरी करने का कोई कारण नहीं है। भले ही, सरकार जनगणना अधिनियम, 1948 के अनुसार जनगणना करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, लेकिन इसमे आवधिकता का अभाव है। हमें दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने की आवश्यकता है। जैसे जापान में जहां जनगणना कानून परिभाषित आवधिकता के साथ जनगणना को अनिवार्य करता है।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Follow Us: @khanglobalstudies

Census in India

Current Context

The deadline to freeze the administrative boundaries of districts, tehsils and towns, among others, has been extended till December 31, ruling out the Census exercise before the 2024 General Elections.

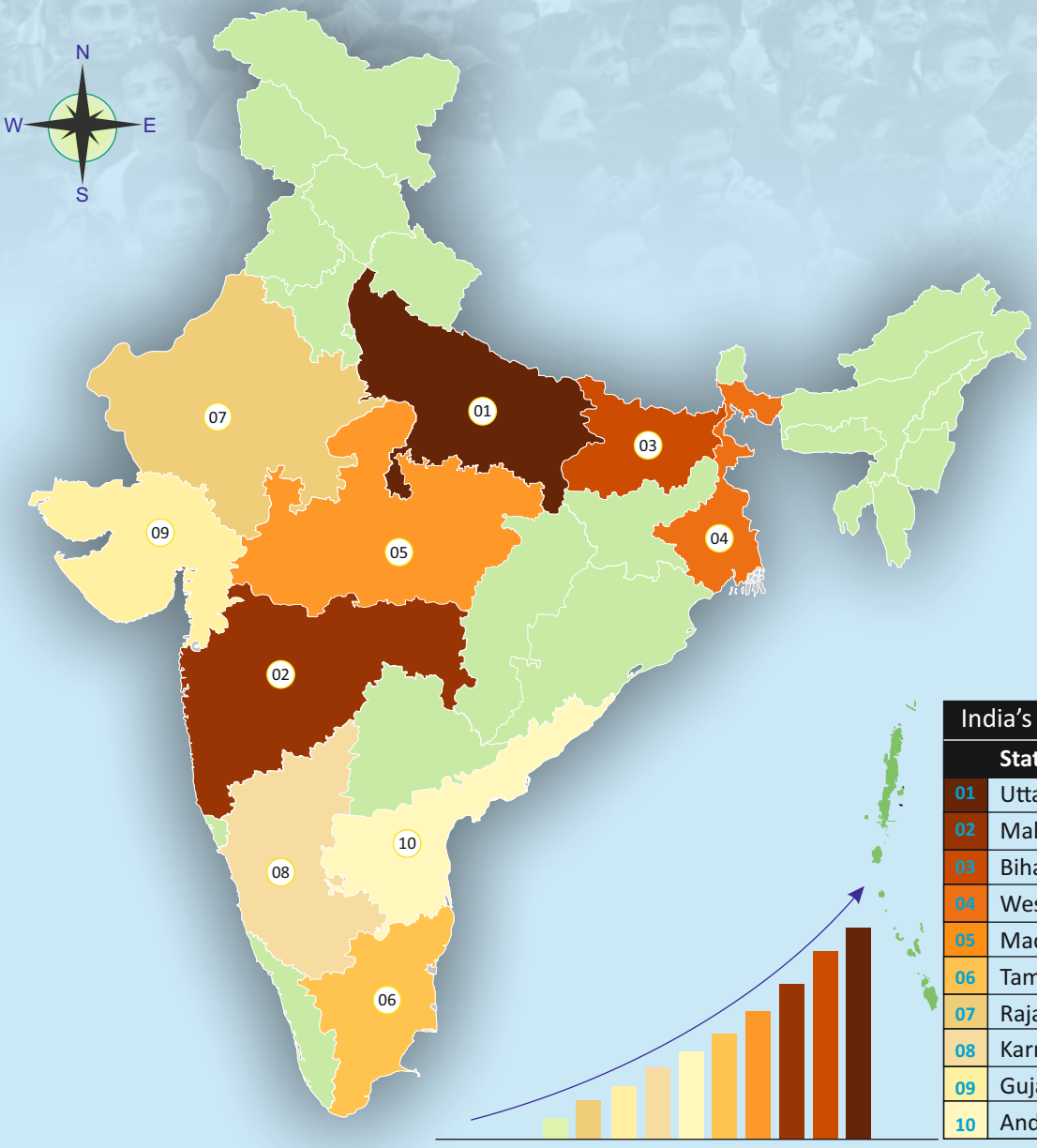

India's Top 10 Most Populous States		
	State	Total Population
01	Uttar Pradesh	199,812,341
02	Maharashtra	112,374,333
03	Bihar	104,099,452
04	West Bengal	91,276,115
05	Madhya Pradesh	72,626,809
06	Tamil Nadu	72,147,030
07	Rajasthan	68,548,437
08	Karnataka	61,095,297
09	Gujarat	60,439,692
10	Andhra Pradesh	49,386,799

Follow Us: @khanglobalstudies

About Census

1. The Indian Census is the largest single source of statistical information on various characteristics of the people of India.

2. The **first census** was conducted non-synchronously in 1871 and the first synchronous census was held across different parts of the country (undivided India) in 1881.

3. The **responsibility** of conducting this exercise is with the **Office of the Registrar General** and **Census Commissioner of India**, Ministry of Home Affairs.

4. Census organization was set up on an ad-hoc basis for each census till the year 1951 census.

5. The Census Act was enacted in 1948 to provide a plan for conducting population census along with the duties and responsibilities of census officers.

6. The Population Census is a Union Subject under **Article 246** of the Indian Constitution.

Census Operations : The Census Operations in India have been carried out in two phases:

First Phase: House Listing and Housing Census

It provides comprehensive data on the conditions of human settlements, housing deficit and consequently the housing requirements to be taken care of in the formulation of housing policies.

Second Phase: Population Enumeration

Each person is enumerated and her/his individual particulars like Age, Marital status, Religion, Scheduled Caste/Scheduled Tribe, Mother tongue, Education level, Disability, Economic activity, Migration, Fertility (for female) are collected.

Significance of Census

- **Important source of information:** The decadal census not only captures increases in population, households, family units, but also gives **detailed granular data** on distribution of age, literacy, fertility and migration.
- **Upliftment of vulnerable sections**: The Census data are used to determine the number of seats to be reserved for SCs and STs in the Parliament, State legislatures, local bodies, and government services.
- **Assessment of policies:** The impact of various programmes like Swachh Bharat Abhiyan, PM-GKAY can be assessed.
- **Assessment of social indicators**: The Census data helps assess literacy and educational levels, employment and income, migration, etc.
- **Grants to states**: The Finance Commission provides it on the basis of population figures available from the Census data.
- **Research** using India's census data has produced thousands of doctorates, new insights into historic policies (both blunders and successes), assisted in various fields, and area. Besides, the census data has also provided a reliable economic history of the nation.

Census 2021

- There was a delay in the conduct of Census 2021 due to the outbreak of COVID-19 pandemic.

Implications of the Delay

01 **Migration data**: Data on the latest estimate is necessary especially after witnessing the pandemic induced reverse migration in some states.

02 **Inefficiency in social disbursement:** The current delay in Census data would continue to deprive more than 10 crore people of subsidised food entitlements, with the biggest gaps in Uttar Pradesh and Bihar, with 2.8 crore and 1.8 crore projected exclusions, respectively.

03 Various **other government schemes** like pensions for the elderly could miss their target by a huge margin since accurate census estimates are not available.

04 In the absence of the census, **accountability of the government** can't be ensured and conclusively known such as houses built under PM AWAS Yojana, toilets constructed under Swachh Bharat, etc.

05 **Age composition:** The pandemic impact on age distribution in severely affected areas would be of interest as it would give an indirect estimate on the number of deaths. Due to lack of Census data, it is impossible to either validate or reject the various estimates of the number of deaths due to the pandemic.

06 **International image:** Our South Asian neighbours have conducted their censuses despite COVID difficulties, which can paint India in bad light.

How will Census 2021 be Different from the Previous Censuses?

01 The Census data will be collected digitally i.e. on Mobile App thus data will be instantaneously ready for processing.

Also, a self-enumeration facility will be provided for the first time. **02**

03 Information of households headed by a person from the transgender community and members living in the family will be collected.

For the questions involving descriptive/non-numeric entries, a separate code directory containing possible responses and codes for each such question has been prepared for use by the enumerators. **04**

Way Forward

With the pandemic behind us, there is no reason to delay the census any further. Even though the government is bound legally to conduct the census according to the Census Act, 1948, but the periodicity is missing. We need to follow the best practices around the world such as in Japan where the Census law mandates a census with defined periodicity.

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Follow Us: @khanglobalstudies